आयकर संदर्भ

प्रेम चंद पंडित और एस. एस. संधावालिया न्यायमूर्ति के समक्ष

आयकर आयुक्त- *अपीलकर्ता।*

बनाम

सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट, यमुनानगर,

उत्तरदाता।

1965 का आयकर संदर्भ संख्या 54

16 दिसंबर, 1970

भारतीय आयकर (1922 का XI) - धारा 10 (2) (xv) - एक करदाता द्वारा भुगतान किया गया पेशेवर कर - क्या व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकार्य कटौती.

माना जाता है कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (2) के खंड (xv) के तहत, केवल वही व्यय कवर किया जाता है जिसे करदाताओं ने अपने व्यवसाय के संचालन या बेहतरी के लिए विशेष रूप से खर्च किया है या निर्धारित किया है। यदि कोई कर केवल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यवसाय को चला रहा है, तो वह इस खंड द्वारा कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि कर उस व्यक्ति के व्यवसाय करने का परिणाम है। यदि उसने वह व्यवसाय नहीं किया होता, तो उस पर कर नहीं लगाया जाता। एक करदाता द्वारा भुगतान किया गया पेशेवर कर उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने का परिणाम है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त कर एक व्यय है जो करदाता द्वारा अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया है। इसलिए किसी निर्धारिती द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में भुगतान किया गया पेशेवर कर व्यवसाय व्यय के रूप में अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत स्वीकार्य कटौती नहीं है।

(पैरा 6)

आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली पीठ द्वारा आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 66(1) के तहत 1964-65 के आरए सं.964 में जुलाई, 1964 के अपने फैसले के तहत आकलन वर्ष 1959-60 के लिए

1963-64 के आईटीए संख्या 4614 से उत्पन्न कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए संदर्भ।

पीठ ने कहा, "चाहे तथ्यों के आधार पर और मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह राशि 1,00,000 करोड़ रुपये रही हो।पेशेवर कर के मद में भुगतान किए गए 250 रुपये के भुगतान को करदाता के मूल्यांकन में कटौती के रूप में स्वीकार्य किया गया थी ?

डी.एन. अवस्थी और बी.एस. गुप्ता, वकील, अपीलकर्ता के लिए।

एस.सी. सिब्बल आर. सी. सेतिया,प्रतिवादी के लिए वकील।

निर्णय।

पी.सी. पंडित, न्यायमूर्ति —कानून का निम्नलिखित प्रश्न राय के लिए हमारे पास भेजा गया है;

क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर पेशेवर कर के रूप में भुगतान की गई 250 रुपये की राशि करदाता के आकलन में कटौती के रूप में स्वीकार्य थी?

2. सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट, यमुनानगर, जिला अंबाला, निर्धारिती, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आकलन वर्ष 1959-60 है और प्रासंगिक लेखा अवधि 31 अगस्त 1958 को समाप्त होने वाला वर्ष है। करदाता ने 250 रुपये की कटौती का दावा किया, जो उसने पेशेवर कर के रूप में भुगतान किया था। आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त दोनों ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (4) के प्रावधानों के मद्देनजर इस राशि को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने हालांकि इसे स्वीकार्य कटौती माना क्योंकि करदाता को अपना कारोबार जारी रखने के लिए इस कर का भुगतान करना पड़ता था। यह निष्कर्ष **सिम्भोली शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, यूपी और वीपी**[1] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए दिया गया था। आयकर आयुक्त ने तब एक आवेदन किया जिसमें ट्रिब्यूनल से कानून के कुछ प्रश्नों को राय के लिए इस न्यायालय को भेजने की आवश्यकता थी, हालांकि, ट्रिब्यूनल ने केवल उपर्युक्त प्रश्न का उल्लेख किया।

3. करदाता ने पंजाब व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग और रोजगार अधिनियम, 1956 के तहत इस कर का

[1] XLV L.T.R 125.

भुगतान किया; और इसने अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत इस कटौती का दावा किया। धारा 10 के प्रासंगिक भाग में लिखा है-

> "10. व्यवसाय (1) कर किसी निर्धारिती द्वारा उसके द्वारा किए गए किसी व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के लाभ और लाभ के संबंध में 'व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत देय होगा;
>
> 2 ऐसे लाभ या लाभ की गणना निम्नलिखित भत्ते देने के बाद की जाएगी, अर्थात्:-
>
> * * • »
>
> * * *
>
> (xv) कोई भी व्यय जो किसी खंड (i) से (xiv) में वर्णित प्रकृति का भत्ता न हो; और यह करदाता के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत खर्चों की प्रकृति में नहीं है, जो इस तरह के व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या खर्च किया गया है।

4. करदाता का मामला यह था कि यह व्यय न तो कार्रवाई 10 (2) के किसी भी खंड (i) से (xiv) में वर्णित प्रकृति का भत्ता था और न ही यह करदाता के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में था, बल्कि इसे पूरी तरह से और विशेष रूप से उसके व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित या खर्च किया गया था। करदाता को अपना कारोबार जारी रखने के लिए पेशेवर कर का भुगतान करना पड़ता था। इसलिए, यह कर पूरी तरह से धारा 10 (2) (xv) के प्रावधानों द्वारा कवर किया गया था और संबंधित मूल्यांकन में कटौती के रूप में स्वीकार्य था।

5. दूसरी ओर, राजस्व द्वारा लिया गया रुख यह था कि करदाता अधिनियम की धारा 19 (4) के प्रावधानों के मद्देनजर इस कटौती का दावा नहीं कर सकता था, जिसका प्रासंगिक हिस्सा है:

> "उप-धारा (2) के खंड (xv) के खंड (ix) में कुछ भी किसी व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के लाभ या लाभ पर लगाए गए किसी भी उपकर, दर या कर के कारण भुगतान की गई किसी भी राशि के भत्ते को अधिकृत करने के लिए नहीं समझा जाएगा या इस तरह के किसी भी लाभ या लाभ के आधार पर या अन्यथा के अनुपात में मूल्यांकन किया जाएगा।

उनका मामला यह था कि चूंकि यह कर निर्धारिती के व्यवसाय के मुनाफे या लाभ पर लगाया गया था या किसी भी मामले में इस तरह के किसी भी लाभ या लाभ के अनुपात में या अन्यथा मूल्यांकन किया गया था, इसलिए, अधिनियम की धारा 10 (4) के प्रावधानों के मद्देनजर इस राशि को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. पहला सवाल यह है कि क्या करदाता द्वारा स्थापित मामला अधिनियम की धारा 10 (2) (xv) के तहत आएगा। वह इस कर की छूट का दावा तभी कर सकता है जब वह यह दिखा सके कि यह कर पूरी तरह से और विशेष रूप से अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित या खर्च किया गया व्यय था। दूसरे शब्दों में, क्या यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा व्यय था जो निर्धारिती द्वारा विशेष रूप से अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया था? यह कहना बिल्कुल अलग है कि करदाता पर कर लगाया गया था, क्योंकि उसने अपना कारोबार जारी रखा था। इस खंड के दायरे में केवल वही खर्च आएगा, जिसे करदाता ने अपने कारोबार के संचालन या बेहतरी के लिए विशेष रूप से खर्च किया है या निर्धारित किया है। यदि कोई कर केवल इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यवसाय को कर रहा था- यह, मेरे विचार में; इस खंड द्वारा कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कर उस व्यक्ति के व्यवसाय करने का परिणाम है। अगर उसने वह कारोबार नहीं किया होता तो उस पर टैक्स नहीं लगता। इस मामले में करदाता के कारोबार को आगे बढ़ाने का नतीजा था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उक्त कर एक व्यय था जो करदाता द्वारा अपने व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया गया था।

7. मैंने ऊपर जो विचार व्यक्त किया है, वह मद्रास उच्च न्यायालय के **आयकर आयुक्त बनाम किंग एंड पार्ट्रिज**[2] मामले में दिए गए पूर्ण पीठ के निर्णय से समर्थित है। वहां विचार के लिए सवाल यह था कि क्या मद्रास सिटी म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 111 के तहत भुगतान किए गए पेशे कर को अधिनियम की धारा 11 के अर्थ के भीतर निर्धारितियों के "केवल पेशे के प्रयोजनों के लिए किए गए व्यय के रूप में" कर योग्य आय से उचित कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। आयकर आयुक्त की राय थी कि दावा की गई कटौती एक स्वीकार्य वस्तु नहीं थी। इस प्रश्न पर अपनी राय देते हुए, विद्वान न्यायाधीशों ने टिप्पणी की: -

[2] A.I.R 1926 Mad 368

"हमारे सामने रखे गए प्रश्न का उत्तर, नगर पालिका द्वारा लगाए गए पेशे कर की प्रकृति पर हमारी राय में निर्भर करता है। यदि व्यवसाय-कर निर्धारिती की आय से नगरपालिका को दिया गया योगदान है, तो यह स्वयं आयकर के समान ही खड़ा होगा जो सरकार को किया जाने वाला ऐसा भुगतान है। यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की आय का आकलन करने में उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर में कटौती नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो भुगतान किया जाता है वह आय का एक हिस्सा है और उस आय या लाभ को अर्जित करने के लिए व्यय नहीं है। यह **एश्टन गैस कंपनी बनाम अटॉर्नी जनरल**[3],में स्थापित किया गया था और प्रस्ताव हमारे सामने स्वीकार कर लिया गया है। तो फिर पेशा-कर क्या है? क्या यह करदाता की आय से किया गया भुगतान है या यह एक ऐसा व्यय है जिसे उसे अपनी आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए करना होगा? हमारी राय है कि यह पहला है और बाद वाला नहीं।

* ♦ ♦ *

अब कर की प्रकृति व्यक्तिगत कर के साथ भिन्न नहीं हो सकती है। सरकार के अधीन नियुक्तियां करने वाले व्यक्तियों के मामले में हमें यह निर्धारित करना असंभव लगता है कि वे अपना वेतन अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए व्यवसाय-कर का भुगतान करें। ** **

कर का उचित आधार अर्जित आय है। इस दृष्टिकोण से पेशे-कर के भुगतान को "ऐसे पेशे के उद्देश्य के लिए व्यय" नहीं माना जा सकता है, हालांकि यह इसके संबंध में किया गया है। "उद्देश्य के लिए" शब्द लॉर्ड डेवी द्वारा **स्ट्रॉन्ग एंड कंपनी बनाम वुडीफील्ड**[4] के मामले में लगाए गए थे, जहां अभिव्यक्ति "व्यापार के उद्देश्यों के लिए" थी। उनके प्रभुत्व ने देखा:

> "ये शब्द मुझे किसी व्यक्ति को व्यापार आदि में आगे बढ़ने और लाभ कमाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रतीत होते हैं। मेरे विचार से जिन संवितरणों की अनुमति दी गई है वे इस उद्देश्य के लिए किए गए हैं। यह पर्याप्त नहीं है कि संवितरण व्यापार के दौरान किया जाता है, या उससे उत्पन्न होता है, या उससे जुड़ा होता है, या व्यापार के मुनाफे से किया जाता है। यह लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया जाना चाहिए। उस दृष्टिकोण के बाद हम मानते हैं कि पेशे कर का भुगतान

[3] (1906) A.C.10.
[4] (1906) A.C.443.

धारा 11 के अंतर्गत नहीं आता है।

8. इस मामले के इस दृष्टिकोण में, दूसरे प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या व्यवसाय-कर किसी व्यवसाय के लाभ या लाभ पर लगाया जाता है या राजस्व द्वारा दिए गए ऐसे लाभ या लाभ के अनुपात में या अन्यथा मूल्यांकन किया जाता है; या यह किसी करदाता के आकलन वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों पर लगाया जाता है, भले ही उसने कोई लाभ कमाया हो या नहीं, जैसा कि करदाता के वकील द्वारा तर्क दिया गया है।

9. तदनुसार, मैं हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दूंगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.एस. संधावालिया, न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ओमेश

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी